

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी - गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 001/2015(रा.प्रा.प.) (GCMS 2015/00053)	दायर दिनांक 22.04.2015	निर्णय दिनांक 05.12.2023
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

1. भैरू पिता हीरा जाति गुर्जर आयु 60 वर्ष धन्धा खेती निवासी गुर्जर खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. रतनलाल पिता बालु गुर्जर आयु 40 वर्ष धन्धा खेती निवासी गुर्जर खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. मोहनलाल पिता भंवरलाल जाति गुर्जर आयु 42 वर्ष धन्धा खेती निवासी गुर्जर खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. उंकारलाल पिता जीतुलाल जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष धन्धा खेती निवासी गुर्जर खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रार्थीगण**बनाम**

1. छोगानाथ पिता गोकलनाथ जाति कालबेलिया आयु 50 वर्ष निवासी मनोहर खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. श्रीमती सवागीबाई पत्नी छोगानाथ जाति कालबेलिया आयु 45 वर्ष निवासी मनोहर खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- छोगालाल जाट
अनुपस्थित
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)

अधिवक्ता प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 1, 2
अप्रार्थी संख्या 3

कार्यवाही एलोटमेंट निरस्त करने बाबत**-:: निर्णय ::-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि-प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण गुर्जर खेडी तहसील निम्बाहेडा के खातेदार काश्तकार है और



गुर्जर खेड़ी के मवेशी के स्वामी है और प्रार्थीगणों के पास पशु धन है और ये पशु गुर्जर खेड़ी में चरनौट जमीन में चरते है और इस चरनौट जमीन के सम्पूर्ण देखभाल नियन्त्रण स्थानीय ग्राम पंचायत बागेड़ा घाटा के पास है। विपक्षी संख्या 01 को ग्राम गुर्जर खेड़ी की आराजी नम्बर 16/2 रकबा 02 बीघा आंवटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा आंवटन क्रमांक 23 दिनांक 26.06.2002 को आंवटित हुई और भू-आंवटन के बाद विपक्षी संख्या 01 व 02 ने इस आंवटित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं किया और इस आंवटित भूमि के चारो ओर सरकारी चरनौट है और ये भूमि चरनौट क्षेत्र में ही आती है जिसमें कदीम से सभी गुर्जर खेड़ी के निवासी के सभी मवेशी चरती है और विपक्षी संख्या 01 व 02 ने इस भूमि पर कोई काशत नहीं की और एलोटमेन्ट के शर्तों के अनुसार इस भूमि को आबाद नहीं की और इस भूमि पर एक दिन भी खेती नहीं की और अभी हाल ही में दिनांक 27.08.2014 को जेसीबी मशीन लाकर चरनौट की भूमि में जबरदस्ती खाई लगाकर चरनौट की भूमि पर कब्जा करने लगा तो प्रार्थीगणों को इसकी जानकारी हुई और प्रार्थीगणों ने सरकारी रिकार्ड देखा तो यह मालुम हुआ की विपक्षी संख्या 01 व 02 को उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा ने दिनांक 26.06.2002 को 02 बीघा भूमि आंवटित हुई जिसका नम्बर 16/02 है जिसका नामान्तकरण संख्या 243 है। जिससे यह भूमि विपक्षीगणों के गैरखातेदारी में दर्ज हुई है, चूंकि यह भूमि सार्वजनिक चारागाह के बीच में स्थित है जहां ग्रामवासियों के मवेशी चरते है इसलिये प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आंवटन से व्यथित है इसलिये उक्त आंवटन को जन सामान्य पुख्ता आधारों पर निरस्त कराने के अधिकारी है। आराजीयात नम्बर 16/2 जिसका नया नम्बर 34 हैं को विपक्षी संख्या 01 व 02 को दिनांक 26.06.2002 को आंवटन हुआ और इस भूमि पर विपक्षी संख्या 02 का कोई कब्जा नहीं रहा। इसलिये बगैर कब्जा प्राप्त किये जो दिखावटी आंवटन हुआ है, प्रार्थीगण समस्त ग्रामवासी गुर्जर खेड़ी के हित इस आंवटन को निरस्त कराने के अधिकारी है। आंवटन आदेश के बाद विपक्षी संख्या 01 व 02 ने आंवटन के शर्तों के अनुसार कभी भी काशत नहीं की और न ही इसे उपजाऊ बनाया और ना ही इसे काबिल काशत बनाया इस प्रकार स्पष्ट रूप से आंवटन में वर्णित शर्तों का विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा उल्लंघन करने के कारण यह आंवटन आदेश दिनांक 26.06.2002 को प्रार्थीगण निरस्त कराने के अधिकारी है। यह भूमि ग्राम गुर्जर खेड़ी के सार्वजनिक महत्व की भूमि चरागाह जो आराजी नम्बर 30, 31, 32 एवं 33 से घिरी हुई है और से आराजी नम्बर 34 भी चरागाह का ही भाग है जिस पर कोई कब्जा विपक्षी संख्या 01 व 02 ने न किया और न है फिर भी जो आंवटन हुआ है वह विधि विधान के विरुद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी ने आंवटन आदेश की शर्तों की पालना नहीं की है बल्कि इस भूमि की आड़ में अन्य भूमि जो चरनौट है अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहा है। इस प्रकार इस आधार पर प्रार्थीगण इस आंवटन आदेश को निरस्त कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगणों का इस आंवटन की पूर्व में जानकारी नहीं थी क्योंकि विपक्षी ने कभी भी इस पर काशत नहीं की। जैसे ही विपक्षी ने आकर चरनौट की भूमि पर नाजायज कब्जा



करना चाहा तो प्रार्थीगणों ने उन्हें रोका तो प्रार्थीगणों को जानकारी हुई और जानकारी मिलते ही यह आंवटन आदेश नामान्तकरण संख्या 243 के अनुसार आराजी नम्बर 16/2 को प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आधारों पर निरस्त कराने के अधिकारी है और ये कार्यवाही पेश की जा रही है। आंवटन आदेश मूल काफी प्रयास के बाद भी नहीं मिला इसलिये नामान्तकरण संख्या 243 की प्रमाणित प्रति प्राप्त इस आवेदन पत्र के साथ पेश की जा रही है। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आंवटन दिनांक 26.06.2002 सूची संख्या 23 को निरस्त करने की कृपा करें।

इस पर प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से दिनांक 22.12.2015 उनके अधिवक्ता बगदीराम धाकड़ हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2018/09 दिनांक 10.01.2018 से मूल पत्रावली प्राप्त हुई है जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 03.07.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। न्यायालय आदेश दिनांक 03.07.2018 से तहसीलदार निम्बाहेडा से प्रकरण में मौका एवं रेकार्ड की वास्तविक स्थिति के संबंध में बाद जांच रिपोर्ट के आदेश दिये गये। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/361 दिनांक 15.04.2021 से प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 28.11.2023 को अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये एवं बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्षकारान की सहमति से प्रकरण में बहस पत्रावली सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली में बताया कि ग्राम प्रार्थीगण गुर्जर खेड़ी तहसील निम्बाहेडा के खातेदार काश्तकार हैं और गुर्जर खेड़ी के मवेशी के स्वामी हैं। विपक्षी संख्या 01 को ग्राम गुर्जर खेड़ी की आराजी नम्बर 16/2 रकबा 02 बीघा आंवटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा आंवटन क्रमांक 23 दिनांक 26.06.2002 को आंवटित हुई और भू-आंवटन के बाद विपक्षी संख्या 01 व 02 ने इस आंवटित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं किया और इस आंवटित भूमि के चारों ओर सरकारी चरनौट है और ये भूमि चरनौट क्षेत्र में ही आती है जिसमें कदीम से सभी गुर्जर खेड़ी के निवासी के सभी मवेशी चरती है और विपक्षी संख्या 01 व 02 ने इस भूमि पर कोई काश्त नहीं की और एलोटमेन्ट के शर्तों के अनुसार इस भूमि को आबाद नहीं की और इस भूमि पर एक दिन भी खेती नहीं की। यह भूमि सार्वजनिक चारागाह के बीच में स्थित है जहां ग्रामवासियों के मवेशी चरते हैं इसलिये प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आंवटन से व्यथित है। आराजी नम्बर 16/2 जिसका नया नम्बर 34 हैं को विपक्षी संख्या 01 व 02 को दिनांक 26.06.2002 को आंवटन हुआ और इस भूमि पर विपक्षी संख्या 02 का कोई कब्जा नहीं रहा। आंवटन आदेश के बाद विपक्षी संख्या 01 व 02 ने आंवटन के शर्तों के अनुसार कभी भी काश्त



नहीं की और न ही इसे उपजाऊ बनाया और ना ही इसे काबिल काश्त बनाया इस प्रकार स्पष्ट रूप से आंवटन में वर्णित शर्तों का विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा उल्लंघन करने के कारण यह आंवटन आदेश दिनांक 26.06.2002 निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 (राजकीय अधिवक्ता) ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर आंवटन नियमों की पूर्ण पालना की जाकर विधिवत आंवटन किया गया है जिससे अधीनस्थ आंवटन सलाहकार समिति के निर्णय दिनांक 26.06.2002 में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने की गुंजाईश नहीं होकर पुष्टि किये जाने योग्य है। इसके साथ ही राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बताया कि यह भूमि ग्राम गुर्जर खेड़ी के सार्वजनिक महत्व की भूमि चरागाह जो आराजी नम्बर 30, 31, 32 एवं 33 से घिरी हुई है और से आराजी नम्बर 34 भी चरागाह का ही भाग है जिस पर कोई कब्जा विपक्षी संख्या 01 व 02 ने न किया और न है फिर भी जो आंवटन हुआ है वह विधि विधान के विरुद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी ने आंवटन आदेश की शर्तों की पालना नहीं की है बल्कि इस भूमि की आड़ में अन्य भूमि जो चरनौट है अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहा है। इस प्रकार इस आधार पर प्रार्थीगण इस आंवटन आदेश को निरस्त कराने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आंवटन दिनांक 26.06.2002 सूची संख्या 23 को निरस्त करने की कृपा करें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में RRD 1982 पेज संख्या 237, RRD 1981 पेज संख्या 644, RRD 1983 पेज संख्या 53, RRD 1983 पेज संख्या 319 एवं RRD 1989 पेज संख्या 654 न्यायिक दृष्टांत पर दृष्टिपात कराया एवं प्रार्थी/निगराकार का प्रार्थना स्वीकार किये जाने की ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आंवटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आंवटन की व्यवस्था की गई है कि :-

101. Allotment of land for agricultural purposes – (1)Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.



(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.

(3) XXX delted XXX]

(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

- (i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated from the same source, preference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);
- (ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;
- (iii) by drawing lots:]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.

14. Condition of Allotment. –

(1) The allotment of land under these rules shall be on a Gair Khatedari tenancy with a right to ultimate conferment of Khatedari rights after the expiry of 10 years provided the allottee fulfills during this period the terms and conditions of allotment until Khatedari rights are conferred. The allottee shall have all the rights and be subjected to all liabilities of a Gair Khatedar tenant under the Tenancy Act: [Provided also that the allotment of land may be cancelled at any stage by the Collector before the expiry of a period of 10 years, if the land is required for public purpose:

[Provided further the no such order to the prejudice of such person shall be passed without giving him an opportunity of being heard.]

(2) Rent at the sanctioned rent rate applicable to the land, or if the land applied for and allotted is unassessed, at the lowest class of Barani land in the village for irrigated land at the Chahi or Nehri rates, as the case may be. for Chahi or Nehri irrigated lands of the village shall be payable from the first year of allotment.

(3) The allottee shall have to cultivate at least 50% of the land in the first year- of allotment and the remaining area in the second year: Provided that this period may be extended by the Tehsildar by one year if, due to unforeseen causes over which the allottee had no control, he was unable to cultivate the land within the stipulated period.

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

(5) The allottee shall pay to the State Government the price of the walls and permanent, structures if any, existing on the land, as also the price of trees standing on the land at rates prescribed by rules made under section 80 and 81 of the Tenancy Act.

(6) Before acquisition of Khatedari rights the allottee shall not construct any permanent structures or buildings other than a tank, well or dwelling a house



- within the meaning of an "improvement" as defined by clause (19) of section 5 of the Tenancy Act.
- (7) In case of land situated within a radius of 10 miles of Jaipur City the allottee shall also pay the rate of Fifteen rupees and 25 paise per hi glia:
Provided that, no such price shall be charged if the number of trees standing in a bigha of land is less than five.
- (8) The land shall be liable to be resumed by the State Government without, payment of compensation if-
- it is not brought under cultivation strictly in accordance with the condition of allotment and it is not properly utilised;
 - it is sub let or transferred in contravention of the provision of Tenancy Act applicable to Gair Khatedar tenants;
 - it is found that the allottee was not a [landless agriculturist];
 - the allottee makes default in the timely payment of the price referred to in clause 5 of the rule and/or the annual rent: or
 - the allottee makes construction on the land in contravention of the allotment rules.
- [(9) In case the land allotted in grass land or subject to erosion, the allottee shall have to undertake the work of soil conservation as and when directed by an officer of the Agriculture Department authorised in this behalf.]

हमने तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 15.04.2021 का अवलोकन किया। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से प्राप्त मूल अभिलेख का गहनता पूर्वक आद्यौपांत अवलोकन/परिशीलन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि आवंटन किये जाने हेतु विधिवत उद्घोषणा भी जारी नहीं हुई थी तथा आवंटन के वक्त आवंटन हेतु विधिवत कौरम भी नहीं हुई थी तथा विपक्षीगण का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने से भूमि आबाद नहीं करने से आवंटन आदेश जो वैधानिक रूप से भी गलत है, जो निरस्त होने योग्य है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को सूचना दी, तथा राज्य सरकार द्वारा जो सदस्य नियुक्त किये गये हैं, उन सदस्यों ने समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए राज्य सरकार के आदेशानुसार आवंटन किया है, जो सही एवं सत्य है।

तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आराजीयात के आस-पास चरागाह भूमि है इस पर ग्रामवासियान के मवेशी चरते हैं एवं चरागाह पर ग्राम पंचायत बांगेडाघाटा द्वारा मेड-बंदी की हुई है। वक्त आवंटन भूमि गैर-खातेदारी हक के दर्ज हुई। आवंटन की शर्तों की पालना में गैर-खातेदार ने उक्त भूमि को कब्जा काशत कर खातेदारी हक प्राप्त किया। वर्तमान में खातेदार ने उक्त भूमि के चारों ओर पत्थर की बाड बनाकर खेती (काशत) कर रहे हैं। खातेदार द्वारा उक्त आवंटित भूमि को काबिल काशत बना कर काशत की जा रही है। आवंटी द्वारा आवंटन की पालना कर काशत कर रहा है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा इस संबंध में पर्चा मौका दिनांक 16.10.2010 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। पर्चा मौका दिनांक 16.10.2010 में उक्त आराजी आराजी संख्या



34 रकबा 0.43 हैक्टेयर पर खातेदारान का कब्जा काश्त होना अवगत कराया गया है।

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटी को भूमि का कब्जा पटवार हत्का द्वारा दिनांक 05.07.2002 को सौपा जा चुका था। आवंटी का आवंटित भूमि पर उसी का कब्जा होकर उपयोग/उपभोग में ली जा रही है। विपक्षीगण के कब्जा एवं काश्त तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पुष्टि की गई है। जहां तक गैर खातेदारी से खातेदारी का प्रश्न है कृषि भूमि हेतु भू-आवंटन नियम 1970 के प्रावधान अनुसार आवंटी खातेदारी की पात्रता रखता है। आवंटन के 13 वर्षों बाद भूमि आवंटन निरस्तगी के प्रार्थना-पत्र का कोई पुख्ता अभिलेखीय आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आवेदन प्रस्तुत के 13 वर्ष पूर्व भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ हुआ, जिस पर काश्त की जा रही है। उक्त विवरण के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र मिथ्या आधार पर प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो तथ्य प्रार्थना-पत्र में उठाए गए हैं वे पूर्ण रूप से मिथ्या है। विधिवत भूमि की उद्घोषणा जारी होकर सलाहकार समिति की राय के अनुसार आवंटन किया गया है। विपक्षीगण को भूमि का आवंटन विधिवत किया जाना प्रस्तुत अभिलेख से प्रतीत है। छल-कपट या नियमों के विपरीत भूमि आवंटन का होना नहीं पाया जाता है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूपेण चस्पांगी नहीं होते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 350/2002 दिनांक 26.06.2002 में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के सारहीन, बलहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं अप्रार्थीगण का आवंटन यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण भैरूलाल पिता हीरा जाति गुर्जर निवासी गुर्जर खेडी तहसील निम्बाहेडा वगैराह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 को सारहीन, बलहीन व आधारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 350/2002 निर्णय दिनांक 26.06.2002 की पुष्टि की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.12.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

